
	केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)		
	O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX,		
सत्यमेव जयते	वस्तु एवं सेवा कर भवन,	GST Building 7 <sup>th</sup> Floor, Near Polytechnic, Ambavadi, Ahmedabad-380015	
	सातवीं मंजिल, पॉलिटेक्निक के पास		
	आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015		
☎ 079-26305065			☎ फेक्स: 079-26305136

6623706627

क फाइल संख्या : File No : V2/124/GNR/2018-19

ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: AHM-EXCUS-003-APP-94-18-19

दिनांक Date : 11-09-2018 जारी करने की तारीख Date of Issue: 22/10/2018

श्री उमाशंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

C. file

Passed by Shri Uma Shanker Commissioner (Appeals) Ahmedabad

ग अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश : 16-18/REF/S.TAX/NK/2018-19 दिनांक : 30-05-2018 से सृजित

Arising out of Order-in-Original: 16-18/REF/S.TAX/NK/2018-19, Date: 30-05-2018 Issued by: Assistant Commissioner, CGST, Div: Gandhinagar, Gandhinagar Commissionerate, Ahmedabad.

घ अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the Appellant & Respondent

M/s. The Beast Apps (India) Pvt. Ltd.

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

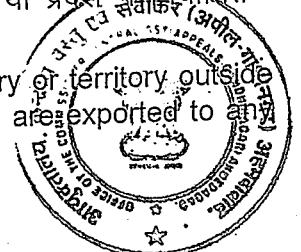
(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4<sup>th</sup> Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क के माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to Country or territory outside India.



- (ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
- (c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-  
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35- षोबी/35-इ के अंतर्गत:-

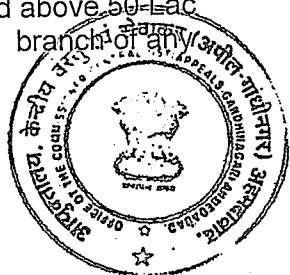
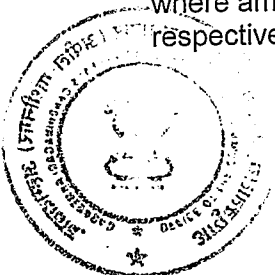
Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016.

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखाकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any



nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्टेट) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1984 की धारा 35फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-2) अधिनियम 2014(2014 की संख्या 29) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 23 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत " माँग किए गए शुल्क " में निम्न शामिल हैं

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होंगे।

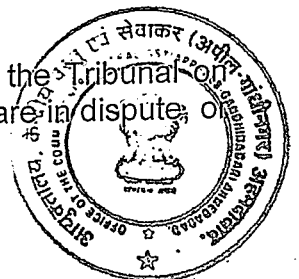
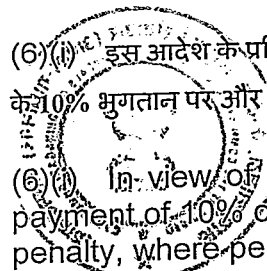
For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



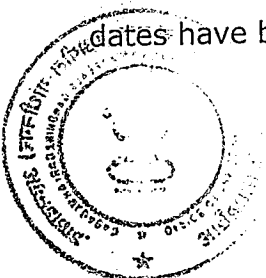
### Order-In- Appeal

This order arises on account of an appeal filed by M/s. The Beast Apps (India) Pvt. Ltd., 104, 1<sup>st</sup> Floor, I.T. Tower-2, Infocity, Nr. Indroda Circle, Gandhinagar (hereinafter referred to as the '*the appellants*' for sake of brevity) against Order-in-Original No. OIO/16-18/Ref/S.TAX/NK/2018-19 dated 30.05.2018 (hereinafter referred to as the '*impugned order*' for the sake of brevity) passed by the Assistant Commissioner, Central GST, Division-Gandhinagar (hereinafter referred to as the '*adjudicating authority*' for the sake of brevity).

2. Briefly facts of the case are that the appellants were registered with the Service Tax Department under the category of Information Technology Software Service and holding Registration No. AACCV3254ASD002. They filed refund claims of ₹ 5,04,707/- on 26.02.2018 for the periods July 2016 to September 2016 (₹ 1,30,676/-), October 2016 to December 2016 (₹ 1,42,175/-) and January 2017 to March 2017 (₹ 2,31,856/-) under Notification number 27/2012-C.E.(NT) dated 18.06.2012 (hereinafter referred to as '*the said Notification*' for sake of brevity) before the proper authority in prescribed format. The adjudicating authority, during scrutiny of the claim, found that the appellants had failed to furnish BRC/FIRC in respect of payments received during the relevant period for export services within the prescribed time limit i.e. before the expiry of one year from the date of receipt of payment in convertible foreign exchange. Accordingly, a show cause notice, dated 18.05.2018, was issued to appellants which was adjudicated by the adjudicating authority vide the impugned order. The adjudicating authority, vide the impugned order, rejected the entire refund claim in terms of provisions of Rule 5 of CENVAT Credit Rules, 2004 read with Section 11B of the Central Excise Act, 1944 made applicable to the Service Tax matter vide Section 83 of the Finance Act, 1994 and Notification No. 27/2012 C.E.(NT) dated 18.06.2012.

3. Being aggrieved with the impugned order, the appellants filed the present appeal before me. The appellants argued that the adjudicating authority has wrongly considered the date of inward remittances realized as available in the BRCs submitted by the appellants. They further contended that the time limits applied, by the adjudicating authority, to all the refund claims was not correct. They stated that the dates of remittance quoted by the adjudicating authority are not correct. In support of their claim, they submitted photocopies of BRCs/FIRCs along with the appeal and requested to set aside the impugned order and award them consequential benefits.

4. Personal hearing in the case was granted on 05.09.2018 wherein Shri Pravin Dhandharia, Chartered Accountant, appeared on behalf of the appellants and reiterated the contents of the appeal memorandum. He stated that the adjudicating authority has not considered the dates of actual remittance and some hypothetical dates have been shown in the impugned order.

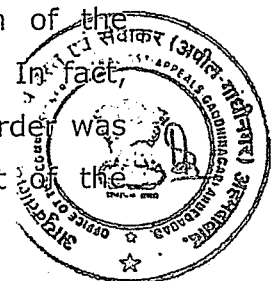
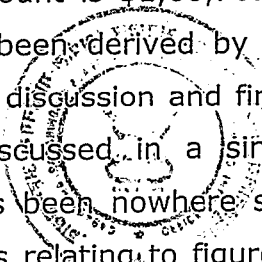


5. I have carefully gone through the facts of the case on records, grounds of the Appeal Memorandum, the Written Submission filed by the appellants and oral submission made at the time of personal hearing. To begin with, I find that there has been a delay occurred in filing the appeal by the appellants. The impugned order was issued on 30.05.2018 and the appellants have filed the appeals on 28.08.2018. I find that the appeals are delayed by 23 days. The appellants filed an application for condonation of delay as the responsible person was indisposed, and I condone the delay and proceed to decide the case on merit.

6. Now, to begin with, I find that the refund claims were rejected on the ground that the appellants failed to file the said claims after lapse of one year from the date of receipt of the foreign remittance. In this regard, I find that the appellants have submitted, before me, photocopies of the related BRCs and thus, to get a better understanding of the situation, I first of all pick up all the BRCs. Going through the BRCs I find that the dates of realization mentioned in the said BRCs differ from the dates mentioned in the impugned orders. A table is placed below to show the difference for more clarity;

Sr. No.	Refund under Rule 5 of CCR, 2004 (₹)	Amount as per invoice (\$)	Actual date of realization as shown in the BRCs	Date of realization shown in the impugned order
1.	1,30,678	54,176	28.12.2016	28.12.2016
2.		53,723	24.01.2017	24.01.2017
3.		52,882	17.07.2017	23.11.2016
4.	1,42,175	52,599	05.07.2017	--
5.		48,413	Awaited	--
6.		47,576	18.12.2017	--
7.	2,31,856	44,812	11.07.2017	27.02.2017
8.		45,032	20.12.2017	--
9.		40,517	18.12.2017	--

7. From the above table, it can be seen that the dates shown by the adjudicating authority, in the impugned order, in serial number 3 and 7 are different from the dates shown in the respective BRCs. From where the said dates were taken by the adjudicating authority is not mentioned in the impugned order. Moreover, the amount received during the period July 2016 to September 2016 has been shown as \$55,921 whereas, actually the amount is \$1,60,781 (54,176 + 53,723 + 52,882). How the amount of \$55,921 has been derived by the adjudicating authority is a mystery. Further, I find that in the discussion and findings portion of the impugned order, the main issue has been discussed in a single paragraph. The observation of the adjudicating authority has been nowhere supported by documentary facts. In fact, looking at the flimsy flaws relating to figures and date, it seems that the order was prepared with a half hearted attitude; which is deplorable on the part of the



adjudicating authority. This kind of avoidable apathy on the part of the departmental officers shows the entire department in a very bad grade.

8. In light of the above discussion, after listening to the arguments of the appellants and going through the impugned order and the grounds of appeal, I come to the conclusion that the adjudicating authority has wrongly rejected the refund claims by applying time limit under the provision of 11B of the Central Excise Act, 1944. Therefore, I set aside the impugned order with consequential relief to the appellants, if applicable.

9. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9. The appeals filed by the appellant stand disposed off in above terms.

*उमा शंकर*

(उमा शंकर)

CENTRAL TAX (Appeals),

AHMEDABAD.

ATTESTED

*S. Dutta*  
(S. DUTTA) 157018

SUPERINTENDENT,

CENTRAL TAX (APPEALS), AHMEDABAD.

To,  
M/s. The Beast Apps (India) Pvt. Ltd.,  
104, 1<sup>st</sup> Floor, I.T. Tower-2,  
Infocity, Nr. Indroda Circle,  
Gandhinagar-382 010.

Copy to:-

1. The Chief Commissioner, Central Tax Zone, Ahmedabad.
2. The Commissioner, Central Tax, Gandhinagar.
3. The Dy. / Asstt. Commissioner, Central Tax, Div- Gandhinagar.
- 4.- The Addl./Joint Commissioner, (Systems), Central Tax, Gandhinagar.
5. Guard file.
6. P.A file.

